

शरद कुमार

बनाम

सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य

11 अप्रैल 2002

(डी.पी. महापात्र और ब्रिजेश कुमार, जे.जे.),

श्रम कानून:

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 धारा 2(एस), 2(के), 10 और 12 कार्यकर्ता-कौन है- सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति का निर्धारण- विशेष या विविध- आयोजित, यह सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति से पता लगाया जाना चाहिए- केवल पदनाम पर विचार करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

बोर्ड/न्यायालयों/न्यायाधिकरण- उचित सरकार- क्षेत्राधिकार- दायरा और धारित सीमा को विवाद का संदर्भ, एक कर्मचारी द्वारा खुद को कर्मकार के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किए गए मुख्य कर्तव्य और सहायक कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए- तथ्यात्मक मामले, मौखिक साक्ष्य सहित सामग्री आवश्यक है जांच की जानी चाहिए- ऐसे मामलों का निर्णय उपयुक्त/राज्य सरकार की तुलना में औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा अधिक उचित रूप से किया जा सकता है।

अपीलार्थी- कर्मचारी 'क्षेत्र बिक्री कार्यकारी के रूप में कार्यरत था। नियोक्ता ने बिना किसी जांच के और बिना किसी शर्त के अपनी सेवाओं को समाप्त कर दिया। उसे मामले में कारण दिखाने का अवसर मिलता है। समाप्ति आदेश को चुनौती दी गई और मामले को सुलह अधिकारी के पास भेजा गया, जिन्होंने एक विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत

की। रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार ने विवाद को निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय को भेजने से इनकार कर दिया। अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए इस न्यायालय के समक्ष अपील करें।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि वह विविध कर्तव्यों का पालन कर रहा था और राज्य सरकार ने केवल उसके द्वारा धारण किए गए पद के पदनाम के आधार पर विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय को भेजने से इनकार करने में त्रुटि की और क्या अपीलार्थी कर्मचारी था या नहीं, तथ्यों की जांच शामिल है और इसलिए, राज्य सरकार अंततः मामले पर निर्णय नहीं ले सकी।

अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत कर्मचारी के रूप में। प्रत्यर्थी- नियोक्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी का योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की किसी भी श्रेणी में नहीं आता था।

प्रत्यर्थी के लिए यह तर्क दिया गया था- राज्य सरकार/ उपयुक्त सरकार धारा 10 (1) के तहत निर्णय लेने के लिए सक्षम है। अधिनियम के अनुसार, क्या कोई विवाद औद्योगिक विवाद था या क्या कर्मचारी अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ के भीतर कर्मचारी था।

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या राज्य सरकार ने अपीलार्थी के अनुरोध को अस्वीकार करके अपने अधिकार क्षेत्र का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया। औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय को विवाद के संदर्भ के लिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनों ने निर्वहन/समाप्ति से संबंधित

विवाद को संदर्भित करने से इनकार कर दिया। औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम के लिए निर्णय के लिए अपीलार्थी की सेवा न्यायालय क्योंकि अपीलार्थी धारा के अर्थ में 'कर्मचारी नहीं है। 2 (एस) औद्योगिक विवाद अधिनियम। संदर्भ को अस्वीकार करने का आदेश विवाद प्रत्यर्थी द्वारा पारित किया गया था- राज्य सरकार अपने अभ्यास में अधिनियम की धारा 12 (5) के साथ पठित धारा 10 (1) के तहत शक्ति। (1061- एफ-जी)

1.2. इसे एक स्वीकृत सिद्धांत के रूप में लेना होगा कि आने के लिए धारा 2 (एस) में 'कामगार' अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर व्यक्ति में उल्लिखित कार्यों के किसी एक प्रकार का निर्वहन करना होगा, खंड का पहला भाग। यदि व्यक्ति पहले भाग के भीतर नहीं आता है, तब इस धारा के आगे के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या वह धारा के उत्तरार्ध भाग के तहत बाहर रखे गए श्रमिकों के किसी भी वर्ग के भीतर आता है। (1065- डी),

2.1. जब किसी कर्मचारी को एक विशेष प्रकार का कर्तव्य सौंपा जाता है और विवाद की तारीख तक उसी का निर्वहन कर रहा है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि क्या वह एक कर्मचारी है। धारा 2 (एस) का अर्थ। यदि दूसरी ओर कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति बहुआयामी है, तो विचार के लिए एक और सवाल उठ सकता है कि इनमें से कौन सा कर्तव्य उनका प्रमुख कर्तव्य है और कौन से सहायक कर्तव्य उनके द्वारा किए गए हैं। प्रश्न का निर्णय करते समय, कर्मचारी का पदनाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है और निश्चित रूप से इसमें निर्णायक नहीं होता है। यह मामला कि वह अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत एक कर्मचारी है या नहीं। (1065- ई, एफ, जी)

2.2. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश की पुष्टि करने में गलती की थी।

राज्य सरकार द्वारा पारित संदर्भ की अस्वीकृति केवल प्रत्यर्थी, यानी क्षेत्र बिक्री कार्यकारी द्वारा धारण किए गए पद के पदनाम पर ध्यान देती है। राज्य सरकार या यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा निर्वहन किए गए विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में जाने का कोई प्रयास नहीं किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ के भीतर आया था। राज्य सरकार ने केवल उनके द्वारा धारण किए गए पद के पदनाम पर विचार किया जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मामलों से परे है। नियुक्ति आदेश से जिसमें कुछ कर्तव्यों की गणना की गई है जो- अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वह नहीं आया था। अधिनियम की धारा 2 (एस) के पहले भाग के भीतर। (1072- एफ- एच)

एम/एस. में एंड बेकर (इंडिया) लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी, आकाशवाणी (1967) एससी 678, बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अ. बर्मा शेल मैंगैगमेंट स्टाफ एसोसिएशन और अन्य, (1970), 3 एस.सी.सी. 378, निर्मल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1984), एससीसी 407 एस.के. मैनी बनाम एम/एस कैरोना साहू कंपनी लिमिटेड और अन्य, (1994), 3 एस.सी.सी. 510, पर भरोसा किया।

एच.आर. आद्यान्थया और अन्य, वी. सैंडोज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य, (1994), 5 एससीसी 737

3.1. प्रश्न का निर्धारण- क्या अपीलार्थी एक कर्मचारी है या तथ्यात्मक मामलों की जांच की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए मौखिक साक्ष्य सहित सामग्री पर विचार करना होगा। ऐसे मामले में राज्य सरकार अपने ऊपर इस प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति का घमंड नहीं कर सकती थी और यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकती थी कि

प्रतिवादी अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ के भीतर एक कर्मचारी नहीं था, जिससे कार्यवाही समय से पहले समाप्त हो जाती थी। इस तरह के मामले का निर्णय औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय द्वारा पक्षों द्वारा उसके समक्ष रखी जाने वाली सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश स्पष्ट रूप से गलत है और उच्च न्यायालय द्वारा इसे बनाए रखते हुए पारित आदेश अस्थिर है।(1073- ए- बी)

टेलको काफिले के चालक मजदूर संघ और अन्य, बनाम बिहार राज्य और अन्य,

(1989), 3 एस.सी.सी. 271 और एम.पी. सिंचाई कर्मचारी संघ बनाम एम. पी.

और अन्य (1985), 2 एस.सी.सी. 103, पर भरोसा किया।

एस.एल. सोनी बनाम राजस्थान खनिज विकास निगम लिमिटेड जयपुर, (1986)

एल. ए. बी. आई. सी. 468, संदर्भित।

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2622/2002

दिल्ली उच्च न्यायालय के 2000 के सी.डब्ल्यू.पी. सं. 3561 में 10.7.2000

दिनांकित निर्णय और आदेश से।

एस. प्रसाद, राकेश गर्ग, सुश्री श्वेता गर्ग और अशोक कुमार शर्मा अपीलार्थी के लिए।

जे. बी. डी. एंड कंपनी के लिए वी. आर. रेड्डी और सुश्री मीरा माथुर, प्रतिवादी के लिए नं. 2- 4

बी.ए. मोहंती, के. सी. कौशिक और डी. एस. माहरा प्रत्यर्थी नं. 1

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

डीपी महापात्रा, जे.-

अवकाश स्वीकृत।

कर्मचारी द्वारा दायर की गई यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 10.7.2000 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (एनसीटी ऑफ दिल्ली) द्वारा उठाए गए विवाद को संदर्भित करने से इन्कार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया गया है। औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय में अपीलकर्ता केवल इस आधार पर कि वह "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2(एस) के अर्थ के अंतर्गत श्रमिक नहीं है।

मामले में उठाए गए सवालों की सराहना के लिए प्रासंगिक मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार बताई जा सकती है:

अपीलकर्ता एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर था जब उसकी सेवा दिनांक 29.12.1995 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई थी। आदेश उन्हें 28.12.1995 को सूचित किया गया था। अपीलकर्ता की सेवा समाप्त करने का आदेश पारित करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई पूछताछ की गई। हालाँकि, टर्मिनेशन लेटर के साथ उन्हें एक महीने का वेतन भी भेजा गया था। अपीलकर्ता ने सेवा समाप्ति के आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाया। मामले को सुलह के लिए उठाया गया। सुलह अधिकारी ने 23.10.1996 को राज्य सरकार को एक विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुलह अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने दिनांक 14.7.1998 के आदेश के तहत विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम

न्यायालय में निर्णय के लिए भेजने से इन्कार कर दिया। आदेश का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

“दायर किए गए सभी दस्तावेजों और पार्टियों की प्रस्तुतियों और सुलह अधिकारी की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है और यह पाया गया है कि यह नीचे दिए गए कारणों से निर्णय के लिए दिल्ली के औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय के संदर्भ में उपयुक्त मामला नहीं है:

“माना जाता है कि आवेदक को एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव के रूप में नामित किया गया था और वह एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव के कर्तव्यों का पालन कर रहा था, इस प्रकार वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित “कर्मचारी” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।”

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे दिनांक 10.7.2000 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश इस अपील में चुनौती के अधीन है।

आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“प्रतिवादी द्वारा संदर्भ देने से इन्कार करने का एकमात्र कारण यह था कि याचिकाकर्ता जो एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा है, वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एस) के अर्थ के तहत एक श्रमिक नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि वह श्रमिक है या नहीं

इसका निर्णय श्रम न्यायालय को करना चाहिए।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) को पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त एक अधिकारी को अधिनियम की धारा 2(एस) के अर्थ के तहत एक कर्मकार नहीं माना जा सकता है।

खारिज”

राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की सेवा से मुक्ति/समाप्ति से संबंधित विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय में निर्णय के लिए संदर्भित करने से इन्कार करने का एकमात्र कारण है कि वह अधिनियम की धारा 2(एस) के अर्थ के अंतर्गत कर्मकार नहीं है। इसे अलग ढंग से कहें तो चूंकि अपीलकर्ता सेवा समाप्ति के समय एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव का पद संभाल रहा था, इसलिए वह अधिनियम की धारा 2(एस) में परिभाषित अनुसार कर्मकार नहीं था। विवाद के संदर्भ से इन्कार करने का आदेश प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 12(5) के साथ पठित धारा 10(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था।

विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर राज्य सरकार ने संदर्भ के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर सही कदम उठाया और इस तरह कार्यवाही को शुरुआती स्तर पर रोक दिया। क्या यह कानून के तहत निहित क्षेत्राधिकार का उचित और उचित प्रयोग है?

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एस. प्रसाद ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि राज्य सरकार ने केवल अपीलकर्ता द्वारा धारित पद के पदनाम के आधार

पर विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय में निर्णय के लिए भेजने से इनकार करके गलती की है। उनके अनुसार अपीलकर्ता विविध कर्तव्यों का पालन कर रहा था जो अधिनियम की धारा 2(एस) में अभिव्यक्ति कर्मकार की परिभाषा के दायरे में आता था और उसके कर्तव्यों की प्रकृति उक्त धारा में प्रदान किए गए किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आती थी। श्री प्रसाद ने यह भी तर्क दिया कि इस सवाल में कि क्या अपीलकर्ता धारा 2(एस) के तहत एक कर्मकार था या नहीं, इसमें उन तथ्यों की जांच शामिल है जिसे धारा 10(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया जा सका। कार्यवाही करना। श्री प्रसाद ने आगे कहा कि राज्य सरकार को विवाद के फैसले के लिए मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय में भेजना चाहिए था, जिसमें यह सवाल भी शामिल था कि क्या प्रतिवादी अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ के तहत एक श्रमिक था।

इसके विपरीत, नियोक्ता मेसर्स उषा इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वीआर रेड्डी ने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में राज्य सरकार ने विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय में भेजने से इन्कार करके सही किया था। निर्णय के लिए. श्री रेड्डी के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा सुलह कार्यवाही में प्रस्तुत की गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि वह अधिनियम की धारा 2(एस) के पहले भाग में उल्लिखित कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी में नहीं आता था, और इसलिए, धारा 2(एस) में परिभाषित अनुसार वह कर्मकार नहीं था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बी.ए. मोहंती, प्रतिवादी संख्या 1, ने विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय में भेजने से इनकार करने वाले राज्य सरकार के आदेश का समर्थन किया।

उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 10(1) के तहत यह उचित सरकार को निर्णय लेना है कि उठाया गया विवाद एक औद्योगिक विवाद था जैसा कि अधिनियम की धारा 2(के) में परिभाषित किया गया है, जिसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या विवाद नियोक्ता और कामगार के बीच था। श्री मोहंती के अनुसार सरकार के लिए स्वयं को संतुष्ट करना नितांत आवश्यक था कि क्या अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत एक कर्मकार था, और मामले में प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया गया था। इसलिए, आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

प्रारंभ में अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करना सुविधाजनक होगा:

धारा 2(के) “औद्योगिक विवाद” का अर्थ नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, या नियोक्ताओं और कामगारों के बीच, या कामगारों और कामगारों के बीच कोई विवाद या मतभेद है, जो रोजगार या गैर- रोजगार या रोजगार की शर्तों या शर्तों से जुड़ा है। श्रम का, किसी भी व्यक्ति का।

धारा 2(एस) में कर्मकार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“कर्मचारी” का अर्थ किसी भी उद्योग में नियोजित किसी भी व्यक्ति (प्रशिक्षु सहित) से है जो किसी भी शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य को भाड़े या इनाम के लिए करता है, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हों, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के उद्देश्यों में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जिसे उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप बर्खास्त, सेवामुक्त या

छंटनी कर दिया गया हो, या जिसकी बर्खास्तगी, सेवामुक्ति या छंटनी के कारण ऐसा हुआ हो। विवाद, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है-

(प) जो वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन है, या

(पप) जो पुलिस सेवा में या जेल के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, या

(पपप) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है, या

(पअ) जो पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित होने पर, प्रति माह एक हजार छह सौ रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करता है या कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्य रूप से कार्य करता है। प्रबंधकीय प्रकृति।”

धारा 10(1) जिसके तहत चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया था, उसे संयुक्त राष्ट्र के रूप में पढ़ा जाता है।

विवादों को बोर्डों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को संदर्भित करना।

10. (1) जहां उपयुक्त सरकार की राय है कि कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है या आशंका है, वह किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा-

(ए) विवाद को निपटारे को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड को संदर्भित करेगा, या

(बी) विवाद से संबंधित या प्रासंगिक प्रतीत होने वाले किसी भी मामले को जांच के लिए न्यायालय को भेज सकता है, या

(सी) विवाद या किसी भी मामले को, जो विवाद से जुड़ा हुआ या प्रासंगिक प्रतीत होता है, यदि यह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित है, तो निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को संदर्भित करेगा, या

(डी) विवाद या विवाद से जुड़ा या प्रासंगिक प्रतीत होने वाला कोई भी मामला, चाहे वह दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित हो, न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण को संदर्भित करेगा:

धारा के प्रावधान मौजूदा मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

अधिनियम की धारा 12 सुलह अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान करती है।

इसकी उप- धारा 4 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी जांच समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, उचित सरकार को उसके द्वारा उठाए गए कदमों को बताते हुए एक पूरी रिपोर्ट भेजेगा। विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने और उसका निपटारा करने के लिए, साथ ही ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा विवरण और वह कारण जिसके कारण, उनकी राय में, समझौता नहीं हो सका।

धारा 12 की उपधारा (5) जिसमें संदर्भ बनाने की शक्ति उपयुक्त सरकार में निहित है, इस प्रकार है:

यदि, उप- धारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने पर, उपयुक्त सरकार संतुष्ट है कि बोर्ड श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के संदर्भ में

कोई मामला है, तो वह ऐसा संदर्भ दे सकती है। जहां उपयुक्त सरकार ऐसा कोई संदर्भ नहीं देती है, वह इसके कारणों को दर्ज करेगी और संबंधित पक्षों को सूचित करेगी।

हमारे सामने यह विवादित नहीं था कि संदर्भ देने या ऐसा करने से इन्कार करने का अधिकार उपयुक्त सरकार में निहित है, जो प्रकृति में प्रशासनिक है और रिपोर्ट और सुलह अधिकारी से प्राप्त सामग्री के अवलोकन पर उसके द्वारा बनाई गई राय पर निर्भर करता है। इस मामले में निर्णय जिस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है वह यह है कि ऐसे मामले में उपयुक्त सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का दायरा और सीमा क्या है?

अधिनियम की धारा 2(एस) में प्रावधानों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि कर्मकार का अर्थ किसी भी उद्योग में नियोजित कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य को भाड़े पर करता है या इनाम में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे बर्खास्त, सेवामुक्त या छंटनी की गई हो।

अनुभाग के उत्तरार्ध में कर्मचारियों के 4 वर्ग शामिल नहीं हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत व्यक्ति, या प्रति माह 1600/- रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाली पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित व्यक्ति या मुख्य रूप से प्रबंधकीय कार्य करने वाला व्यक्ति शामिल है। प्रकृति। इसे एक स्वीकृत सिद्धांत के रूप में लिया जाना चाहिए कि धारा 2(एस) में अभिव्यक्ति कर्मकार के अर्थ में आने के लिए व्यक्ति को अनुभाग के पहले भाग में सूचीबद्ध कार्यों में से किसी एक प्रकार का निर्वहन करना होगा। यदि व्यक्ति धारा के पहले भाग के अंतर्गत नहीं आता है तो आगे के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या वह धारा के उत्तरार्ध के अंतर्गत बाहर किए गए श्रमिकों के किसी वर्ग में आता है। यह प्रश्न कि क्या संबंधित व्यक्ति अनुभाग के

पहले भाग में आता है, यह उसे सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति औरध्या उसके द्वारा निर्वहन पर निर्भर करता है। कर्मचारी के कर्तव्यों को सेवा नियमों या विनियमों या स्थायी आदेश या नियुक्ति आदेश या किसी अन्य सामग्री में वर्णित किया जा सकता है जिसमें उसे सौंपे गए कर्तव्य पाए जा सकते हैं। जब कर्मचारी को एक विशेष प्रकार का कर्तव्य सौंपा गया है और वह विवाद की तारीख तक उसका निर्वहन कर रहा है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि क्या वह धारा 2(एस) के अर्थ के तहत एक कर्मकार है। दूसरी ओर, यदि कर्मचारियों द्वारा निभाए गए कर्तव्यों की प्रकृति विविध है तो विचार के लिए अगला प्रश्न उठ सकता है कि उनमें से कौन सा उसका मुख्य कर्तव्य है और कौन सा उसके द्वारा निष्पादित सहायक कर्तव्य हैं। ऐसे मामले में प्रश्न का निर्धारण उस स्तर पर आसान नहीं है जब राज्य सरकार खुद को संतुष्ट करने के सीमित उद्देश्य के लिए इसमें निहित प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही है कि उठाया गया विवाद धारा 2 (के) के अर्थ के तहत एक औद्योगिक विवाद है या नहीं। अधिनियम का. प्रश्न का निर्णय करते समय, कर्मचारी का पदनाम अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से इस मामले में निर्णायक नहीं है कि वह अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत एक श्रमिक है या नहीं।

इस स्तर पर हम कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं, जिनमें प्रश्न पर इस न्यायालय के साथ- साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया है।

मैसर्स के प्रबंधन में एम/एस और बेकर (इंडिया) लिमिटेड बनाम उनके कर्मकार एआईआर 1967 एससी 678, इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए धारा 2(एस) के प्रावधान की व्याख्या की (जैसा कि यह 1956 के संशोधन से पहले था) कि क्या किया गया मैनुअल या लिपिक कार्य केवल एक आकस्मिक था प्राकृतिक और क्या कर्मचारी धारा के तहत परिभाषित

कर्मकार नहीं था। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

“9. कंपनी का मामला यह है कि मुखर्जी को 1 अप्रैल 1954 से सेवामुक्त कर दिया गया था। उस समय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत” “

शामिल नहीं थे जैसे मुखर्जी जो एक प्रतिनिधि थे। एक “कर्मचारी” को तब किसी भी उद्योग में नियोजित किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था जो भाड़े या इनाम के लिए कोई कुशल या अकुशल मैनुअल या लिपिक कार्य करता था। इसलिए, किसी व्यक्ति को बुलाने से पहले मैनुअल या लिपिक कार्य करना आवश्यक था एक कर्मकार। यह परिभाषा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष विचार के लिए आई और यह लगातार माना गया कि कर्मचारी का पदनाम महान क्षण नहीं था और जो महत्वपूर्ण था वह उसके कर्तव्यों की प्रकृति थी। यदि कर्तव्यों की प्रकृति मैनुअल या लिपिक है तो व्यक्ति को एक कर्मकार माना जाना चाहिए। दूसरी ओर, यदि शारीरिक या लिपिकीय कार्य संबंधित व्यक्ति के कर्तव्यों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, जो उसके मुख्य कार्य के लिए प्रासंगिक लगता है, जो शारीरिक या लिपिकीय नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। कर्मठ बनो। इसलिए, प्रत्येक मामले में कर्तव्यों की प्रकृति से यह देखा जाना चाहिए कि नियोजित व्यक्ति श्रमिक है या नहीं, उस शब्द की परिभाषा के तहत, जैसा कि 1956 के संशोधन से पहले मौजूद था। मुखर्जी के कर्तव्यों की प्रकृति है इस मामले में कोई विवाद नहीं है और इसलिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मुखर्जी धारा 2(एस) के अर्थ के तहत एक

कर्मकार थे जैसा कि प्रासंगिक समय पर था। मुखर्जी को सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति से हमें पता चलता है कि उनका मुख्य काम प्रचार करना था और लिपिकीय का कोई भी मैनुअल काम जो उन्हें करना पड़ता था वह उनके प्रचार के मुख्य काम के लिए आकस्मिक था और वह समय के एक छोटे से हिस्से से अधिक नहीं ले सकते थे। जिसके लिए उन्हें काम करना पड़ा. इन परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि मुखर्जी एक कर्मकार थे, गलत है। ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल इस तथ्य से भटक गया है कि मुखर्जी के पास कोई पर्यवेक्षी कर्तव्य नहीं था और उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के तहत काम करना पड़ता था। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि मुखर्जी के कर्तव्य मुख्य रूप से मैनुअल या लिपिकीय थे। ट्रिब्यूनल ने जो पाया है उससे यह स्पष्ट है कि मुखर्जी के कर्तव्य मुख्य रूप से न तो लिपिकीय थे और न ही मैनुअल। इसलिए, चूंकि मुखर्जी एक श्रमिक नहीं थे, इसलिए उनका मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा और ट्रिब्यूनल के पास उनके पुनर्कथन का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इसलिए, हम अन्य राहों के साथ मुखर्जी की बहाली के निर्देश देने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हैं।" (जोर दिया गया)

इसी तरह का एक प्रश्न बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आया था। बर्मा शेल मैनेजमेंट स्टाफ एसोसिएशन और अन्य, 1970(3) एससीसी 378, जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति मुख्य रूप से पर्यवेक्षी कार्य कर रहा है और संयोगवश या कुछ समय के

लिए कुछ लिपिकीय कार्य भी करता है, तो यह होगा यह माना जाएगा कि वह पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत है, और, इसके विपरीत, यदि किया गया मुख्य कार्य लिपिकीय प्रकृति का है, तो केवल तथ्य यह है कि कुछ पर्यवेक्षी कर्तव्य भी संयोगवश या उसके द्वारा किए गए कार्य के एक छोटे अंश के रूप में किए जाते हैं। एक क्लर्क के रूप में उसके रोजगार को पर्यवेक्षी क्षमता में परिवर्तित करें। इस न्यायालय ने सेल्स इंजीनियरिंग प्रतिनिधि और जिला बिक्री प्रतिनिधि सहित कर्मचारियों के कई वर्गों पर विचार करते हुए, औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्रियों पर यह माना कि कर्मचारियों के ये दोनों वर्ग धारा 2(एस) में अभिव्यक्ति "कर्मचारी" के अर्थ में नहीं आते हैं। यहां यह नोट करना प्रासंगिक है कि यह न्यायालय मामले में औद्योगिक न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र, बॉम्बे द्वारा पारित अंतरिम पुरस्कार की वैधता पर विचार कर रहा था।

उपर्युक्त दो तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों और अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा एचआर आद्यांतया और अन्य बनाम के मामले में एक संविधान पीठ द्वारा निर्णय लिया गया। सैंडोज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य 1994(5) एससीसी 737 ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

“23. हालाँकि, बाद के मामलों में निर्णय, जैसे, एसके वर्मा, डेल्टन केबल, और सिबा गीगी मामलों में मई और बेकर, विमको और बर्मा शेल मामलों में पहले के निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया गया और वही विवाद, जैसे कि, यदि ए वह व्यक्ति मैनुअल, लिपिक, पर्यवेक्षी या तकनीकी की किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, वह कर्मकार होने के लिए केवल इसलिए अर्हता प्राप्त करेगा क्योंकि वह परिभाषा के चार अपवादों में से किसी में भी शामिल नहीं है, प्रचारित किया गया था

और हालांकि पहले के निर्णयों में इसे नकारात्मक माना गया था। स्वीकार किया गया। इसके अलावा, उन मामलों में एलआईसी के विकास अधिकारी, कारखाने के गेट पर सुरक्षा निरीक्षक और क्रमशः स्टेनोग्राफर- सह- लेखाकार को उन मामलों के तथ्यों पर कामगार माना गया। यह इस न्यायालय का निर्णय है, ए. सुंदरम्बल मामले में, जिसमें बताया गया कि मई और बेकर मामले में निर्धारित कानून अभी भी अच्छा था और अस्वीकार्य नहीं था।

24. इस प्रकार हमारे पास तीन तीन- न्यायाधीशों की बेंच के फैसले हैं, जिन्होंने यह विचार किया है कि एक व्यक्ति को श्रमिक बनने के लिए योग्य होने के लिए वह काम करना चाहिए जो चार श्रेणियों में से किसी एक में आता है, अर्थात्, मैनुअल, लिपिक, पर्यवेक्षी या तकनीकी। और दो दो- न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले, जिनमें उक्त तीन फैसलों में से एक या दूसरे का हवाला देकर उक्त कानून को दोहराया गया है। इसके विपरीत, हमारे पास तीन तीन- न्यायाधीशों की बेंच के फैसले हैं जो मई और बेकर के फैसलों का जिक्र किए बिना हैं। डब्ल्यूआईएमसीओ और बर्मा शेल मामलों ने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया है, जो स्पष्ट रूप से नकारात्मक था, अर्थात्, यदि कोई व्यक्ति उक्त परिभाषा के चार अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है तो वह आईडी अधिनियम के अर्थ के तहत एक कर्मकार है। ये फैसले भी उन मामलों में मिले तथ्यों पर आधारित होते हैं। इसलिए, उन्हें उन तथ्यों तक ही सीमित रहना होगा। इसलिए आज कानून में जो स्थिति है वह यह है कि आईडी अधिनियम के तहत कामगार बनने वाले व्यक्ति को किसी भी श्रेणी के काम करने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए,

जैसे कि मैनुअल, अकुशल, कुशल तकनीकी, परिचालन, लिपिक या पर्यवेक्षी। यह पर्याप्त नहीं है कि वह परिभाषा के चार अपवादों में से किसी में भी शामिल नहीं है। हम उक्त व्याख्या को दोहराते हैं।" (जोर दिया गया)

निर्मल सिंह बनाम में पंजाब राज्य और अन्य 1984 (सप्ल) एससीसी 407 यह न्यायालय इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए अधिनियम की धारा 2(एस) और 12(5) के प्रावधानों की व्याख्या करता है कि क्या सहकारी बैंक का शाखा प्रबंधक एक श्रमिक है, इस प्रकार देखा गया:

"3. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए श्री एनडी गर्ग द्वारा की गई शिकायत कि श्रम आयुक्त को अपने निर्णय के समर्थन में कारण बताना चाहिए था, उचित है। श्रम आयुक्त ने आदेश में जो कुछ भी कहा है वह यह है कि अपीलकर्ता द्वारा धारित पद "कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। यह, वास्तव में, वह निष्कर्ष है जिस पर श्रम आयुक्त पहुंचे, लेकिन उस निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। हमारी राय है कि श्रम आयुक्त को ऐसा करना चाहिए कारण बताए हैं कि वह इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे कि अपीलकर्ता औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अर्थ के तहत "कर्मचारी" नहीं है।"

इस न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए प्रतिवादी नंबर 2 को श्रम आयुक्त, चंडीगढ़ को अधिनियम की धारा 12 के तहत एक संदर्भ बनाने का निर्देश दिया।

टेलको कॉन्वॉय ड्राइवर्स मजदूर संघ और अन्य बनाम के मामले में बिहार राज्य और अन्य 1989 (3) एससीसी 271 इस न्यायालय ने धारा 10(1) के प्रावधान की

व्याख्या इस प्रकार की:

“13. हालांकि विवाद आकर्षक है, हमें खेद है, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि, अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, उपयुक्त सरकार का कार्य एक प्रशासनिक कार्य है और यह कोई न्यायिक या अर्ध- न्यायिक कार्य नहीं है, और यह कि इस प्रशासनिक कार्य को करने में सरकार विवाद के गुणों में नहीं पड़ सकती है और लिस का निर्धारण अपने ऊपर नहीं ले सकती है, जो निश्चित रूप से उसे प्रदत्त शक्ति से अधिक होगा। अधिनियम की धारा 10 देखें राम अवतार शर्मा बनाम हरियाणा राज्य (1985) 3 एससीसी 189, म.प्र. सिंचाई कर्मचारी संघ बनाम मप्र राज्य (1985) 2 एससीसी 103 और शंभू नाथ गोयल बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा, जालंधर (1978) 2 एससीसी 353

14. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सरकार द्वारा विवाद का निर्णय करना उचित नहीं था। जहां, मौजूदा मामले की तरह, विवाद यह है कि विवाद उठाने वाले व्यक्ति श्रमिक हैं या नहीं, यह अधिनियम की धारा 10(1) के तहत अपने प्रशासनिक कार्य के अभ्यास में सरकार द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मप्र सिंचाई कर्मचारी संघ मामले में माना गया है, ऐसे असाधारण मामले हो सकते हैं जिनमें राज्य सरकार, मांग की उचित जांच करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि मांगें या तो विकृत या तुच्छ हैं और

संदर्भ के योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, सरकार को संदर्भ में गिरावट की दृष्टि से मांग की जांच करने का प्रयास करना चाहिए और जब भी सरकार वैध विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए ट्रिब्यूनल की शक्तियों को हड़पने का प्रयास करती है, और सरकार को अनुमति देने के लिए अदालतें हमेशा सतर्क रहेंगी। ऐसा करना अधिनियम की धारा 10 और धारा 12 (5) को निष्प्रभावी बना देगा।” (जोर दिया गया)

म.प्र. सिंचाई कर्मचारी संघ बनाम में मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 1985 (2) एससीसी 103 बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स बनाम बॉम्बे राज्य एआईआर 1964 एससी 1617 के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह माना गया था कि उपयुक्त सरकार को प्रथम दृष्टया गुणों पर भी विचार करने से रोका गया है। विवाद के बारे में जब यह सवाल तय करता है कि संदर्भ देने की उसकी शक्ति का प्रयोग धारा 12(5) के साथ पढ़ी गई धारा 10(1) के तहत किया जाना चाहिए या नहीं, तो इस न्यायालय ने माना कि न्यायालय ने इसे उसी में स्पष्ट कर दिया है। निर्णय दिया गया कि यह तथ्यों के विवादित प्रश्नों का निर्णय करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण का एक प्रांत था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

“5... इसलिए, राज्य सरकार को मांगों की पेटेंट तुच्छता की जांच करने के लिए एक बहुत ही सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुए, इसे एक नियम के रूप में समझा जाना चाहिए, कि श्रमिकों द्वारा की गई मांगों का निर्णय न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए निर्णय लें। धारा 10 उपयुक्त सरकार को यह निर्धारित करने की अनुमति देती है कि क्या विवाद मौजूद है या इसकी आशंका है और फिर इसे गुण-दोष के आधार पर न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करें। सीमांकित

कार्य हैं (1) संदर्भ, (2) न्यायनिर्णयन। जब एक संदर्भ को विशेष दलील पर खारिज कर दिया जाता है कि सरकार अतिरिक्त बोझ नहीं उठा सकते, यह न्यायनिर्णयन का गठन करता है और इस प्रकार एक प्रशासनिक प्राधिकारी अर्थात् उपयुक्त सरकार द्वारा एक अर्ध- न्यायिक न्यायाधिकरण की शक्ति को हड़प लेता है। हमारी राय में, संदर्भ को अस्वीकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए कारण उसकी शक्तियों से परे हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत सरकार। राज्य सरकार ने इस मामले में जो किया है वह इसमें शामिल प्रश्न की खूबियों की प्रथम दृष्टया जांच नहीं है। यह कहना कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, बिना आवश्यक साक्ष्य के और कर्मचारियों को इस निष्कर्ष का खंडन करने का अवसर दिए बिना एकतरफा निर्णय लेना है। यह वस्तुतः मांग पर ही अंतिम निर्णय के समान है। मांग को कभी भी विकृत या तुच्छ नहीं माना जा सकता। इस प्रकार निकाला गया निष्कर्ष कर्मचारियों से ट्रिब्यूनल के समक्ष साक्ष्य रखने और मांग की तर्कसंगतता को साबित करने का अवसर छीन लेता है।” (जोर दिया गया)

एसके मैनी बनाम में एम.एस. कारानो साहू कंपनी लिमिटेड और अन्य (1994)
3 एससीसी 510 इस अदालत ने धारा (2) (पअ) की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:-

“9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमें यह

प्रतीत होता है कि कोई कर्मचारी औद्योगिक धारा 2(एस) के तहत कामगार है या नहीं विवाद अधिनियम को उसके कर्तव्यों और कार्यों की प्रमुख प्रकृति के संदर्भ में निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना आवश्यक है और कोई भी शर्त निर्धारित करना संभव नहीं है- जैकेट फॉर्मूला जो सभी मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों और कार्यों की वास्तविक प्रकृति के विवाद का फैसला कर सकता है। जब एक कर्मचारी को धारा 2(एस) के तहत कर्मकार की परिभाषा में गिनाए गए प्रकार के काम करने के लिए नियोजित किया जाता है। उचित वर्गीकरण के तहत उसे एक श्रमिक के रूप में मानने में शायद ही कोई कठिनाई हो, लेकिन औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों की जटिलता में अक्सर एक से अधिक प्रकार के काम करने के लिए काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि कर्मचारी किस वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा, यह तय करने के लिए कि वह कर्मकार की परिभाषा में आता है या इससे बाहर जाता है। इस संबंध में, बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। बर्मा शैल प्रबंधन स्टाफ एसोसिएशन। अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ एएसएसएन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक ने इस न्यायालय द्वारा यह माना है कि पर्यवेक्षण शब्द और इसके व्युत्पन्न सटीक आयात के शब्द नहीं हैं और इन्हें अक्सर संदर्भ के प्रकाश में समझा

जाना चाहिए, क्योंकि जब तक नियंत्रित नहीं किया जाता है तब तक वे मैनुअल कार्य के रूप में आसानी से सरल निरीक्षण और दिशा को कवर करते हैं। दूसरों के शारीरिक कार्यों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्ति के साथ। दोनों विद्वान वकीलों द्वारा यह सही तर्क दिया गया है कि किसी कर्मचारी का पदनाम अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और जो महत्वपूर्ण है वह कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों की प्रकृति है। निर्धारक कारक संबंधित कर्मचारी के मुख्य कर्तव्य हैं, न कि संयोगवश किए गए कुछ कार्य। दूसरे शब्दों में, मूलतः वह कार्य क्या है जो कर्मचारी करता है या सारतः उसे क्या करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस दृष्टिकोण से देखने पर, यदि कर्मचारी मुख्य रूप से पर्यवेक्षी कार्य कर रहा है, लेकिन संयोग से या कुछ समय के लिए कुछ मैनुअल या लिपिकीय कार्य भी करता है, तो कर्मचारी को पर्यवेक्षी कार्य करने वाला माना जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि मुख्य कार्य मैनुअल, लिपिकीय या तकनीकी प्रकृति का है, तो केवल यह तथ्य कि कुछ पर्यवेक्षी या अन्य कार्य भी कर्मचारी द्वारा संयोगवश किया जाता है या कार्य समय का केवल एक छोटा सा हिस्सा कुछ पर्यवेक्षी कार्यों के लिए समर्पित है, कर्मचारी ऐसा करेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस) में परिभाषित कर्मकार के दायरे में आते हैं।"

(जोर दिया गया)

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसएल सोनी बनाम के मामले में राजस्थान खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर, (1986) लैब आईसी 468, एससी अग्रवाल, जे.

(जैसा कि वह तब थे) इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि क्या एक सहायक प्रबंधक (लेखा) धारा 2(एस) के तहत " ") अधिनियम में याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार कर लिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है और याचिकाकर्ता के लिए उचित उपाय औद्योगिक विवादों की धारा 10 के तहत संदर्भ लेना है। अधिनियम, ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

“मेरे विचार में श्री रंगराजन द्वारा आग्रह की गई उपरोक्त दलील को स्वीकार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में पार्टियों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि क्या याचिकाकर्ता अधिनियम के पारित होने के समय अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत एक श्रमिक था। उनकी सेवाओं को समाप्त करने वाला आक्षेपित आदेश। उक्त प्रश्न में सहायक प्रबंधक (लेखा) के रूप में कार्य करते समय याचिकाकर्ता द्वारा निर्वहन किए जा रहे कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में तथ्यों का निर्धारण शामिल है। ऐसा निर्धारण केवल साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन कार्यवाहियों में उक्त प्रश्न पर उचित निर्णय नहीं दिया जा सकता है और याचिकाकर्ता के लिए जो उचित उपाय उपलब्ध था, वह एक औद्योगिक विवाद उठाना था और इसे अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायनिर्णयन के लिए भेजा जाना था। पहला तर्क आग्रह किया गया इसलिए, श्री सिंघवी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

(जोर दिया गया)

निर्णयित मामलों में निर्धारित सिद्धांतों की कसौटी पर मामले का परीक्षण करते

हुए हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने केवल राज्य सरकार द्वारा पारित संदर्भ की अस्वीकृति के आदेश की पुष्टि करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी। प्रतिवादी द्वारा धारित पद का पदनाम अर्थात् एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस प्रश्न का निर्धारण कर्मचारी द्वारा सौंपे गए या निर्वहन किए गए कर्तव्यों के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि केवल उसके द्वारा धारित पद के पदनाम पर। हम यह नहीं पाते हैं कि राज्य सरकार या यहां तक कि उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा निर्वहन किए गए विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में जाने का कोई प्रयास किया है कि क्या वह अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ में आता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार ने केवल उनके द्वारा धारित पद के पदनाम पर विचार किया जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मामलों से परे है। नियुक्ति आदेश दिनांक 21/22 अप्रैल 1983 से विंच में कुछ कर्तव्य गिनाए गए हैं जिनका निर्वहन अपीलकर्ता को करना पड़ सकता है, इससे यह नहीं माना जा सकता कि वह अधिनियम की धारा 2(एस) के पहले भाग के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा विचार है कि प्रश्न के निर्धारण के लिए तथ्यात्मक मामलों की जांच की आवश्यकता होती है जिसके लिए मौखिक साक्ष्य सहित सामग्री पर विचार करना होगा। ऐसे मामले में राज्य सरकार प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति अपने ऊपर नहीं रख सकती और यह मान सकती है कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 2(एस) के अर्थ के तहत काम करने वाला नहीं है, जिससे कार्यवाही समय से पहले समाप्त हो जाती है। ऐसे मामले का निर्णय औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय द्वारा पक्षों द्वारा उसके समक्ष रखी जाने वाली सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश स्पष्ट रूप से गलत है और उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखते हुए पारित आदेश टिकाऊ नहीं है।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। सिविल रिट याचिका संख्या 3561/2000

में उच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2000 के आदेश को निरस्त किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रतिवादी नंबर 1, को अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या अपीलकर्ता अधिनियम के तहत एक श्रमिक है, निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय को। अपीलकर्ता उत्तरदाताओं से रुपये की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। मामले की लागत और सुनवाई शुल्क के लिए 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये)।

एस.के.एस

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजीव जांगिड़, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।